Government in respect of norms for distribution and release of Central plan assistance;

(b) if so, details of serious lacunae and inequities pointed out by Karnataka; and

(c) what are the corrective steps proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) Presumably, the Hon'ble Member is referring to norms for allocation of Central assistance. Suggestions on this subject have been received from Chief Ministers of several States including Karnataka, Central Assistance to non-Special Category States is formula based. The formula approved at the NDC meeting in December, 1991 takes into consideration their suggestions and gives due weightage to population, per capita income, tax effort, fiscal management, performance in relation to national objectives and special problems.

Declaration of some Districts in Uttar Pradesh as 'Zero-Industry Districts'

51. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to declare some districts in Uttar Pradesh as 'Zero-Industry districts';

(b) if so, what are the names of the such districts; and

(c) what are the norms for declaring districts as 'zero-industry districts'?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) The following districts of Uttar Pradesh were declered "no industry districts" in 1971:—Banda, Fatehpur, Hamirpur, Jalaun, Jaunpur, Sultanpur, Kanpur Dehat, Chamoli, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Uttar Kashi, Almora, Pithoragarh, Dehradun, National,

'No industry districts' are those districts where no medium or large scale industry exists.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का पुनर्गठन किया जाना

52. **श्री राम जेठमलानी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को मार्च, 1991 के अन्त तक भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है ; यदि हां, तो कितनी राशि का वित्तीय घाटा हुआ ;

(ख) क्या सरकार ने इस भारी वित्तीय घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार निगम के कायकरण का जिसमें उसके कारखानों की उत्पादकता, उनकी खरीद, विपणन, प्रशासनिक व्यवस्था और उनका व्यय तथा निगम को पुनर्गठित करना भी सम्मिलित है, व्यापक अध्ययन करने के लिए पनल नियुक्त करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और यदि हां, तो कब तक ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत : (क) जी हां। मार्च, 1991 के अन्त तक एन. टी सी को 2016.27 करोड़ रु. के संचित निवल घाटा हुआ।

(ख) एन टी सी मिलों में घाटों के लिए मुख्य कारण हैं, अप्रचलित मशीन, कम उत्पादकता, फालतू श्रमिक बल, घटिया काय व्यवस्था, कम दाम तथा उपयोग, अपर्याप्त आधुनिकीकरण तथा कार्यशील पूंजी के लिए निधियों की कमी आदि।

(ग) और (घ) पैनल की कोई आवश्यकता नहीं है। एन टी सी ने

सर्वांगीण सुधार के लिए व्यापक प्रस्ताव पहले से ही प्रस्तुत किए हैं।

सूती वस्त्रों को औद्योगिक समिति भी अपने सुझावों पर कार्य कर रही है।

हथकरघा और विद्युतचालित करघा क्षेत्र को धागे की पूर्ति

53. श्री ईश दत्त यादव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान हथकरघा और विद्युत चालित करघा क्षेत्रों द्वारा धागे की कितनी मात्रा की मांग की गई है;

(ख) यह पूर्ति कितनी मात्रा में और किन-किन स्थानों से की गई थी; और

(ग) धागे की पूर्ति में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत: (क) और (ख) हथकरघा और पावरलूम क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत प्रकार के उत्पादन और देश में अधिक बुनाई क्षमता को देखते हुए इन क्षेत्रों में बुनाई कार्यों का स्तर समय-समय पर बदलता रहता है जो सूत के मूल्यों, कपड़ की बिक्री और विभिन्न राज्यों की आर्थिक व अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सूत की मांग का ढाँचा भी इसी प्रकार बदलता रहता है। तथापि हथकरघा और पावरलम विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में सूत की आवश्यकता की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि सूत की आवश्यकता की पूर्ति देशभर में फैली प्राइवेट क्षेत्र की कताई मिलों द्वारा की जाती है। वर्ष 1989–90 और 1990–91 के दौरान देश में विकेन्द्रीकृत बुनाई क्षेत्र में उपभोग के लिए कताई मिलों द्वारा वितरित किया गया स्पन यार्न क्रमश: 1057 मिलियन किलोग्राम और 1159 मिलियन किलोग्राम था। 31 मार्च 1991 को देश के विभिन्न भागों में 26.53 मिलियन तकुऐ थ।

(ग) सरकार विद्यमान सामान्य औद्योगिक नीतियों के अधीन आधुनिकीकरण के अतिरिक्त वर्तमान कताई इकाईयों की क्षमता का विस्तार करने और नई इकाईयों द्वारा क्षमता सृजन करने के लिए प्रोत्साहन देती रही है। देश में सूत का उत्पादन बढ़ाने और कताई मिलों का आधनिकीकरण करने के लिए रोटर अथवा एअर-जेट इकाईयों के द्वारा तुकुओं को बदलने की अनुमति भी दी गई है। तकुओं में प्रयोग क्षमता 1987–88 की 70% से बढ़कर 1990–91 में 79% हो गई। हथकरघा क्षेत्र में आवश्यक मात्रा में हैंक यार्न की उपलब्धता के लिए सरकार हैंक यार्न दायित्व योजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें प्रत्येक सूत उत्पादक को सिविल उपयोग के लिए पक किये गए या कूछ सूत का 50% हैंक के रूप में पैक करना होता है। हथकरघा बुनकरों के लिए सहकारी क्षेत्र में हैंक यार्न के उत्पादन के लिए अतिरिक्त तकुए स्थापित करने के लिए सरकार ने छठी और सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से 64.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की। 1990–91 और 1991–92 में इस कार्य के लिए 4.14 करोड़ रुपये की सहकारी क्षेत्र में ही 6.26 लाख अतिरिक्त तकुए स्थापित हो सके हैं।

Disposal of land held by closed Textile Mills in Public Sector

54.
Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a)whether it is a fact that Government have taken a decision to allow disposal of lands held by closed textile mills in public sector;

(b) what are the terms and conditions for disposal of land held by these closed